केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव के नाम खुला पत्र

श्रममंत्री जी, थोड़ा श्रम ईएसआईसी के लिए भी करो

हरियाणा राज्य से पहली बार कोई केन्द्रीय श्रम मंत्री बना है और वह भी गुड़गांव जिले के गांव जमालपुर (निकट पटौदी) क्षेत्र से। राज्य के इस क्षेत्र में करीब 28 लाख आईपी यानी ईएसआई कवर्ड कामगार रहते हैं, 22 लाख गुड़गांव तथा 6 लाख फ़रीदाबाद में। बीते करीब दो साल से इस पद पर बैठे यादव जी ने विशाल आईपी समुदाय की चिकित्सा सुविधाओं की कोई सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। सुध लेने के नाम पर मानेसर में साढ़े सात एकड़ के भू-खंड पर 500 बेड वाले अस्पताल का शिलान्यास ही किया है। इस भू-खंड के लिये भी खट्टर सरकार ने ईएसआई कॉर्पोरेशन से 120 करोड़ रुपये ठग लिये।

तमाम पूर्व श्रम मंत्री अपने-अपने क्षेत्र के लिये ईएसआई कॉर्पोरेशन फंड का कैसे-कैसे दुरुपयोग कर गये, उसका ज्ञान यदि यादव जी को न हो तो अब जान लें। सन् 2011-12 में तत्कालीन श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चुनाव क्षेत्र गुलबर्गा में 50 एकड़ के भू-खंड पर 1600 करोड़ की लागत से न केवल एक मेडिकल कॉलेज बनवाया बल्कि साथ में डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा पैरा मेडिकल कॉलेज भी बनवा डाला। यह सब तो उन्होंने तब कर डाला जब वहां पर आईपी की संख्या मात्र 10 हजार ही थी। ईएसआई कॉर्पोरेशन की नियमावली के अनुसार 510 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज वहीं खुलेगा जहां आईपी की संख्या कम से कम चार लाख हो। लेकिन यह तो खड़गे का कमाल था जो मात्र 10 हजार आईपी पर ही इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया। फुर्ती इतनी कि 2013 में एमबीबीएस का पहला बैच भी दाखिल कर दिया।

कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा जो हिमाचल के मंडी क्षेत्र से आते हैं, ने अपने प्रभाव के बलबूते 2011 में मंडी में मेडिकल कॉलेज स्थापित करवा दिया। 25 एकड़ के भू-खंड पर बने इस मेडिकल कॉलेज की लागत 800 करोड़ रुपये आई थी। 2014 में बन कर तैयार हो चुकने के बावजूद इस कॉलेज एवं अस्पताल को इसलिये चालू नहीं किया जा सका क्योंकि यहां आईपी की संख्या मात्र 10 हजार ही थी। ईएसआई नियमावली के अनुसार यहां पर गैर आईपी को चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा सकती। कुछ वर्ष झख मार कर, आखिर में मज़दूर के पैसे से बने इस संस्थान को मुफ्त में हिमाचल सरकार के हवाले कर दिया गया।

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार में, राजस्थान के अलवर क्षेत्र से निर्वाचित सांसद सीसराम ओला ने बतौर केन्द्रीय श्रम मंत्री, सन् 2011 में अपने अफ़सरों से पूछा कि वे अपने क्षेत्र के लिये क्या कर सकते हैं? इस पर किसी अफ़सर ने अलवर में मेडिकल कॉलेज बनाने की सलाह दे डाली। बस फिर क्या था, ईएसआई नियमावली को ताक पर रखते हुए, 25 एकड़ के भू-खंड पर 800 करोड़ रुपये की लागत से मात्र 10 हजार आईपी पर ही मेडिकल कॉलेज बना कर खड़ा कर दिया। कॉलेज एवं अस्पताल तो बेशक 2015 में बन कर तैयार हो गये लेकिन पर्याप्त संख्या में आईपी न होने की वजह से कई वर्ष तक चालू नहीं किया जा सका। बीते तीन वर्ष पूर्व ही इसे जैसे-तैसे चालू किया जा सका। इस दौरान जहां आईपी की संख्या में कुछ

बढ़ोत्तरी हुई वहीं गैर आईपी को भी चिकित्सा सेवा देने का प्रावधान किया गया।

ऐसा ही कारनामा बिहटा (पटना) से निर्वाचित भाजपाई सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने 2015 में कर दिखाया। मात्र 20 हजार आईपी के बल बूते 25 एकड़ के भू-खंड पर 800 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण करा डाला। यद्यपि 2017 में काम पूरा हो चुका था लेकिन आईपी संख्या के अभाव में चालू नहीं किया जा सका। सन् 2019 का चुनाव सिर पर आया देख कर रामकृपाल यादव फड़फड़ाए और प्रधानमंत्री मोदी के सामने रोए कि उनके इस अस्पताल को जैसे-तैसे चलवाओ। इस पर मोदी जी ने फौज को आदेश दिया और फौजी डॉक्टरों की टीम वहां पर इसे चलाने की नौटंकी करने लगी; ठीक वैसे ही जैसे कि छांयसा के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में फौज ने किया था। चुनाव के बाद इसे जैसे-तैसे विधिवत चलाया गया।

अब सवाल मौजूदा श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव पर बनता है कि जब सत्तारूढ़ राजनेता नियमों की उल्लंघना करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करा सकते हैं तो इनको क्या मुसीबत आ रही है, अपने गृहक्षेत्र गुड़गांवा के 22 लाख आईपी के लिए दो हजार बिस्तरों वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण करने में? यह हाल तो तब है जब ईएसआई कारपोरेशन के पास डेढ़ लाख करोड़ रुपये का कोष पड़ा हुआ है। इसे खर्च करने के लिए मंत्रीजी को किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, यानी कि मंत्री पद कोई स्थायी सौदा नहीं है, इस पर रहते हुए भी यदि वे अपने क्षेत्र में इतना भी नहीं कर पाते तो कल को लोग दुत्कारेंगे ही। यादव जी से तो अच्छा वे एसी चौधरी कहला गए जो हरियाणा सरकार के मंत्री होते हुए भी 2009 में जैसे तैसे करके फरीदाबाद में वर्तमान ईएसआई मेडिकल अस्पताल का शिलान्यास करा गए।

अपने उक्त पूर्व श्रम मंत्रियों के अलावा यादव जी मोदी सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से भी कुछ सबक सीख सकते हैं। उनके गृह क्षेत्र सनतनगर हैदराबाद का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज भी भयंकर दुर्दशा का शिकार था। दत्तात्रेय उसे किसी भी कीमत पर बेहतरीन संस्थान बनाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने इस काम के लिए एम्स दिल्ली के डॉ. एम श्रीनिवास को चुन कर अपने संस्थान का डीन नियुक्त कर दिया। डॉ. एम श्रीनिवास ने अपने छह वर्ष के कार्यकाल में, ईएसआई कारपोरेशन के उन तमाम बिगड़े, तिगड़े अड़ंगेबाज़ों को सीधा कर दिया जो दिल्ली मुख्यालय में बैठे हरामखोर एवं बेईमान अफसरों के इशारे पर संस्थान को चलने नहीं देना चाहते थे। डॉ. श्रीनिवास को फेल करने के लिए इन लोगों ने संस्थान में हड़ताल तक कर दी थी जिसकी उन्होंने कोई परवाह न करते हुए काम को आगे बढ़ाना जारी रखा। इसे देखकर हड़तालियों को भी अपनी औक़ात समझ में आ गई और घुटनों के बल आ गए। डॉ. श्रीनिवास यह सब केवल इसलिए कर पाए थे कि उनकी पुश्तपनाही पर खुद श्रम मंत्री दत्तात्रेय खड़े थे वरना यह बदमाश गिरोह उन्हें ही चलता कर देता। उनकी योग्यता एवं कर्मठता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें एम्स का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन तक भी नहीं किया था।

दरअसल, ईएसआई कारपोरेशन के तमाम संस्थानों को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए डॉ. श्रीनिवास, डॉ. असीम दास व डॉ. अनिल पांडेय जैसे कर्मठ लोगों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल किसी मंत्री द्वारा उन्हें पहचाने जाकर उनकी पुश्तपनाही करने की।

इसके लिए श्रम मंत्री यादव जी को अधिक कुछ नहीं करना केवल कारपोरेशन मुख्यालय में बैठे हरामखोर मूरखमंडल को ठिकाने लगाकर ढंग के अफसरों को वहां तैनात करना है। कहावत भी है कि नाली की ईंट मुंडेरे पर नहीं लगाई जाती, यहां वही कुछ हो रहा है। डिस्पेंसरी स्तर के डॉक्टर यहां मेडिकल कॉलेजों को दिशा निर्देशन दे रहे हैं। यदि यादव जी इस समस्या से पार पा जाएं तो ईएसआई कारपोरेशन देश में एक बेहतरीन सेवा देने वाला संस्थान हो सकता है।

मुख्यालय में बैठे मूर्खमंडल की समझ एवं कारनामे

ये लोग अपने सामने केवल एक ही लक्ष्य रख कर चलते हैं कि मज़दूरों से अधिक से अधिक वसूला जाए और उन पर कम से कम खर्च किया जाए। इसी सोच के चलते इन लोगों ने सदैव मेडिकल कॉलेज खोले जाने का विरोध किया है। वह बात अलग है कि राजनीतिक दबाव के सामने उनका यह पैंतरा हमेशा नहीं चल पाया। फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज को चलने से रोकने के लिए उन्होंने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। इत्तेफाकन, एक अच्छे डायरेक्टर जनरल के आ जाने से इसका पहला बैच 2015 में चालू हो पाया।

चलने के बाद भी इसके हर उपकरण की खरीद पर हर तरह की अड़चनें इन लोगों ने लगाईं। 30 बेड की आईसीयू तथा डायलिसिस सेंटर तक इन लोगों ने पीपीपी मोड यानी ठेके पर दे दिया। करीब साल भर बाद ही आईसीयू का ठेकेदार वार्ड को ताला लगाकर भाग गया और वर्षों तक यह ताला नहीं खोला जा सका। आज यहां करीब 140 बेड की आईसीयू हमेशा भरी रहती है, इसी तरह डायलिसिस केंद्र को नियमानुसार चलाने का दबाव बनाया गया तो वह ठेकेदार भी छोड़कर भाग गया।

और तो और मुख्यालय में बैठे मूर्खों का यह भी इरादा था कि रेडियोलॉजी (एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे इत्यादि) विभाग को भी ठेके पर दिया जाए। इत्तेफाक से तत्कालीन डीजी एवं श्रम सचिव ने फैकल्टी के तर्कों को समझते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद मामला आया उपकरणों की खरीद का तो इन लोगों का प्रयास था कि घटिया से घटिया एवं पुरानी से पुरानी तकनीक के उपकरण खरीदे जाएं। लेकिन फैकल्टी, डीजी एवं श्रम सचिव को यह समझाने में सफल रही कि बेहतरीन एवं अत्याधुनिक उपलब्ध टेक्नोलॉजी का खरीदा जाना ही सही होगा, तब कहीं जाकर आधुनिक उपकरण खरीदे जा सके।

इनकी अक्ल का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनके दफ्तर में लगे डिस्प्ले स्क्रीन पर पल -पल की सूचना आने के बावजूद यह लोग अपने मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों को ईमेल भेजकर पूछते हैं कि कितने मरीज भर्ती हैं? यानी कि आंख उठाकर डिस्प्ले बोर्ड देखने में भी जोर पड़ता है इनको। इतना ही नहीं अपने अस्पतालों से इन्हें यह पूछने में भी कतई कोई शर्म नहीं आती कि 500 बेड के अस्पताल में कितने स्टाफ की आवश्यकता होती है? जिनको इतना भी नहीं पता तो क्या अब तक वह भाड़ झोंक रहे थे? कितने आईपी पर तथा कितने मरीजों पर कितना स्टाफ होना चाहिए इसका विस्तृत ब्यौरा ईएसआई कारपोरेशन की मैन्यूअल में बाकायदा छपा हुआ है, लेकिन पढ़े कौन? पढ़े तो वह न जिसे कुछ काम करना हो, जिसे काम ही नहीं करना और केवल अड़ंगेबाजी ही करनी है वह तो इसी तरह के सवाल पूछ कर केवल टाइम पास करता है। इतना ही नहीं फैकल्टी द्वारा बार -बार यह सब बताए जाने के बावजूद कोई बात इनकी समझ में नहीं आती।

माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन है कि जितनी जल्दी हरामखोरों से कारपोरेशन का पिंड छुटा पाएं तो मजदूरों पर बड़ा अहसान होगा। लगे हाथ मंत्री महोदय यह भी देखें कि बसई दारापुर के मेडिकल कॉलेज-अस्पताल का बेड़ा गर्क कब से और क्यों हो रहा है? वहां के मरीज फरीदाबाद क्यों भेजे जा रहे हैं ? वहां पर काम न के बराबर होने के बावजूद भी स्टाफ की भरमार क्यों है और फरीदाबाद में काम की भरमार होने के बावजूद स्टाफ की कमी क्यों है?

चिकित्सा क्षेत्र में ईएसआईसी मॉडल से बेहतरीन कोई अन्य मॉडल हो नहीं सकता, यदि इसको सही ढंग से चलाने में रुकावट डालने वाली नौकरशाही को खदेड़ बाहर किया जाए तो।

अपनी मेडिकल जांच के लिये केन्द्रीय श्रम मंत्री पधारे ईएसआई अस्पताल

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) दिल्ली के एम्स तथा अनेकों पंचतारा अस्पतालों की अपेक्षा केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव ने अपनी मेडिकल जांच के लिये एनएच तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर भरोसा किया। यद्यपि अस्पताल के अधिकारियों ने इस बाबत पूरी चुप्पी साध रखी है लेकिन भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार दिनांक 18 मई को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रात: सात बजे मंत्री महोदय अस्पताल पहुंचे। उनके स्वागत के लिये डीन डॉक्टर असीम दास चिकित्सा अधिक्षक डॉ. एके पांडे व अन्य वरिष्ठ फैकल्टीजन मौजूद थे।

सूत्र बताते हैं कि मंत्री जी के लोअर एब्डोमन का अल्ट्रासाउंड, टीएमटी, ईको तथा ईसीजी इत्यादि किये गये। इसके अलावा खून के सेम्पल भी लिये गये। वैसे तो यह सब एक सामान्य जांच प्रक्रिया है जो दिल्ली के किसी भी अस्पताल में हो सकती थी, परन्तु सवाल भरोसे एवं विश्वास का है। बेशक दिल्ली में ही ईएसआई कॉर्पोरेशन का, यहां से भी पुराना मेडिकल कॉलेज अस्पताल मौजूद है लेकिन मंत्रीजी ने उसे किसी लायक नहीं समझा।

करीब आठ बजे मंत्रीजी फारिग होकर जब दवा वितरण स्थल के पास से गुजर रहे थे तो करीब 40-50 मरीज़ दवा लेने की लाइन में लगे हुए थे। विदित है कि अस्पताल के खुलने एवं दवा वितरण का समय सवा नौ बजे का हैं। यदि मंत्रीजी ने इस नजारे को थोड़ी भी गम्भीरता से समझने का प्रयास किया होगा तो वे जरूर समझ गये होंगे कि दिन भर यहां दवा लेने वालों की कैसी दुर्दशा होती होगी? यदि समझ गये होंगे तो इसका समाधान भी वे तुरन्त करने में सक्षम हैं, बशर्ते कि उनकी नीयत हो।

इस अस्पताल में किसी केन्द्रीय श्रममंत्री का यह पहला आगमन नहीं है। इससे पहले तत्कालीन श्रममंत्री संतोष कुमार गंगवार यहां ईलाज करने के लिए बाकयदा दाखिल हुए थे और स्वस्थ होकर गये थे। एक अन्य केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री तेली भी इस अस्पताल को केवल इसलिए देखने के लिए आये थे कि यहां ऐसी खात बात है कि जो कोविड लहर के दौरान उनका द्वारा पूरा जोर लगाने के बावजूद भी वे अपने एक रिश्तेदार को दाखिल नहीं करा पाये थे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।